निवेशकों की पसंद में लखनऊ, अयोध्या और सुल्तानपुर आगे

मध्य यूपी में अवध के जिलों के लिए हुए एमओयू

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में मध्य यूपी के लिए आए निवेश में लखनऊ, अयोध्या और सुल्तानपुर जिले आगे हैं। सबसे कम 650 करोड़ रुपये का निवेश सिद्धार्थनगर में हुआ है। अब तक औद्योगिक विकास की दृष्टि से पिछड़े जिलों में भी उपलब्ध प्राकृतिक संपदा और मानव संसाधन, निवेश अनुकूल माहौल और ढांचागत विकास के बूते हजारों करोड़ रुपये का निवेश होगा।

आंकड़ों पर गौर करें तो कासगंज और सिद्धार्थनगर में निवेश एक हजार करोड़ से कम है। नौ जिलों में एक से दो हजार करोड़, दस जिलों में दो से तीन हजार करोड़, चार जिलों में तीन हजार करोड़ से अधिक, पांच जिलों में चार हजार करोड़ से अधिक रुपये के एमओयू साइन हुए हैं। शेष जिलों में पांच हजार से सात लाख करोड़ रुपये तक के एमओयू हुए हैं। ताजनगरी आगरा 2,18,062 लाख करोड़ के निवेश के लिए 281 एमओयू के साथ दूसरे स्थान पर है। यहां 1,05,515 लोगों को रोजगार मिलेगा। तीसरे स्थान पर रहे लखनऊ में 1,96,261 करोड़ के निवेश के लिए 782 एमओयू हुए हैं। इससे 16,31,543 लोगों को रोजगार देने का दावा है। अयोध्या में 253 एमओयू हुए। इनके जरिये 45,402 करोड़ रुपये के निवेश से 53,472 लोगों को रोजगार की संभावना है।

जिला	निवेश	रोजगार
लखनऊ	196261	1631543
सुल्तानपुर	2432	16210
अयोध्या	45402	53472
बाराबंकी	20076	114126
अमेठी	7966	120365
रायबरेली	2409	11340
बहराइच	4451	82912
सीतापुर	28304	25852
गोंडा	3546	10373
प्रतापगढ़	10913	65284

समझौते जमीन पर उतारने के लिए चुनौतियां भी कम नहीं

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। 33 लाख करोड़ से ज्यादा के करार से जहां प्रदेश में विकास की रफ्तार बढ़ेगी, वहीं इन्हें जमीन पर उतारना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं होगा। इसके लिए जमीन से लेकर समयबद्ध ढंग से सभी विभागों की एनओसी भी मुहैया करानी होगी। अंतर्विभागीय समन्वय भी बेहद जरूरी होगा।

लक्ष्य से ज्यादा निवेश के करार से रोजगार के अवसर भी खूब बढ़ेंगे। यह प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाएगा। आम आदमी के रहन-सहन के स्तर को ऊपर उठाएगा, लेकिन इस निवेश को जमीन पर उतारने के लिए सबसे पहले पर्याप्त लैंड बैंक की व्यवस्था करनी होगी। हालांकि, उद्योग विभाग के अधिकारियों का दावा है कि उनके पास पर्याप्त भूमि है। इस मामले में स्थिति चाहे जो हो, पर उद्यमियों को जमीन निश्चित समय सीमा के भीतर उपलब्ध हो, इसके लिए राज्यस्तर पर विशेष प्रयास करने होंगे। स्थानीय अधिकारियों के कामकाज की लगातार समीक्षा करनी होगी। पर्यावरण, उद्योग और राजस्व समेत तमाम विभागों की एनओसी भी उद्यमियों को निश्चित समय सीमा के भीतर मिले, इसके लिए भी संजीदे प्रयास करने होंगे। कई बार देखने में आया है कि समय से एनओसी न मिलने से उद्यमी अपना मन बदल लेते हैं।

समयबद्ध ढंग से एनओसी और अंतर्विभागीय समन्वय बेहद जरूरी

समीक्षा बैठक जरूरी

उद्यमियों का तो यहां तक कहना है कि निवेश प्रस्तावों पर कम से कम तिमाही समीक्षा बैठक उच्चस्तरीय अधिकारी करें और छमाही समीक्षा बैठक स्वयं मुख्यमंत्री लें। इससे स्थानीय अधिकारियों के स्तर से लापरवाही की गुंजाइश खत्म हो जाएगी। यह भी देखें कि नीतियों में बताई गई सुविधाएं उद्यमियों को समय रहते मिलेंगे। इसमें देरी होने से वे निराश होते हैं और उनकी आर्थिक स्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।